भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2308

25 अप्रैल, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए

पटसन के उत्पादन में बढ़ोत्तरी

2308. श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में पटसन के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में राज्य-वार हुए उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास पटसन/पटसन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है ताकि किसानों की समस्याओं का हल निकाला जा सके;

(घ) क्या देश के पटसन उत्पाद किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाये गये हैं/या उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी)

(क) और (ख): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कच्ची पटसन का राज्य-वार उत्पादन नीचे दिया गया है:-

(180 किग्रा. प्रति गांठ की हजार गांठ)

राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*
अमस	647.5	715.3	625.4	658.0
बिहार	1054.8	1118.4	1164.6	1611
मेघालय	34.6	34.7	34.4	
नागालैंड	1.3	2.0	5.4	
उड़ीसा	19.9	30.4	36.3	32.1
त्रिपुरा	3.7	3.8	4.2	
पश्चिम बंगाल	7872.6	9325.0	8137.5	8600
अन्य	0.0	0.8	1.6	44.9
कुल	**9634.4**	**11230.4**	**10009.4**	**10946.0**

स्रोत: कृषि मंत्रालय, आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय ।

***द्वितीय अग्रिम अनुमान**

(ग): भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर सभी प्रमुख पटसन उत्पादक राज्यों में अपने 171 खरीद केन्द्रों और राज्य सहकारी निकायों के माध्यम से कच्ची पटसन की खरीद के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की नोडल एजेंसी है । भारतीय पटसन निगम ने 12.10.2011 से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रचालन आरंभ किए हैं । 23.02.2012 तक पटसन की विभिन्न ग्रेडों की 127.82 हजार गांठ (2.30 लाख क्विंटल) किसानों से खरीदी हैं । जेसीआई द्वारा कच्ची पटसन की खरीद हेतु मौजूद कार्य तंत्र के कारण मूल्य एमएसपी से नीचे नहीं गिरने दिए जाते हैं ताकि किसानों को कठिनाईयों से बचाया जा सके ।

जहां तक पटसन उत्पादों का संबंध है, इनके लिए कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है ।

(घ) और (ङ.): सरकार पूरे देश में पटसन किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किए हैं/कर रही है । कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार है:-

(i) 11वीं योजना अवधि के दौरान 355 करोड़ रु. के परिव्यय से पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है । जेटीएम के अधीन लघु मिशन **I, II,** तथा **III** के तहत अनेक योजनाएं चल रही हैं जिनसे पटसन उत्पादकों को लाभ हो और उन्हें पटसन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिले । लघु मिशन- **I** का उद्देश्य उपज और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पटसन क्षेत्र में कृषि अनुसंधान और विकास को सुदृढ़ बनाना है । लघु मिशन- **II** का लक्ष्य उत्पादन तथा कटाई पश्चात वाले चरण में उन्नत प्रौद्योगिकी और एग्रोनोमिक प्रक्रिया का अंतरण करना है । लघु मिशन- **III** के अंतर्गत सभी पटसन उत्पादक राज्यों में कच्ची पटसन के लिए बाजार संपर्क प्रदान किया जाता है ।

(ii) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड तथा भारतीय पटसन निगम, पटसन की खेती के लिए बेहतर पटसन बीज विकसित करने तथा एग्रोनोमिकल प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए पटसन और संबद्ध फाइबर प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय संस्थान (एनआईआरजेएएफटी) के साथ परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं ।

(iii) कच्ची पटसन तथा मेस्टा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य हर वर्ष निश्चित किये जाते हैं ताकि अधिक पटसन उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके ।

(iv) भारतीय पटसन निगम तथा राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रमाणित बीज वितरित कर रहे हैं ।

(v) पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने पटसन बोरों में खाद्यान्नों तथा चीनी की अनिवार्य पैकेजिंग के लिए नीति जारी रखी है ।